

Corporation should be wound up, as it has not been a commercially viable organisation. The Committee reiterated this recommendation in its "Action Taken" report on the said sixty-second Report. The committee's recommendation is under Government's consideration.

बीजों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव

2414. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 वर्ष में बीजों के मूल्यों में क्या उतार-चढ़ाव रहा ; और

(ख) मूल्य वृद्धि के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्री ० श्री ० जीर्ण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम जैसे संस्थानों द्वारा बेचे गये मुख्य किस्म के बीजों के मूल्यों में 1972-73 के दौरान आमतौर से कोई भारी घटा-बढ़ी नहीं हुई है। राष्ट्रीय बीज निगम ने गेहूँ के बीज का मूल्य 1971-72 में 170 रुपये से बढ़ा कर 1972-73 में 200 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। बीज उत्पादकों को ऊँचे वसूली मूल्य दिए जाने के कारण यह वृद्धि आवश्यक हो गई थी। जहाँ तक भारतीय राज्य फार्म निगम का मामला है, इस निगम ने मूँग के बीजों का मूल्य 1972-73 में बढ़ाया था।

सुपर बाजार, नई दिल्ली में पूंजी निवेश और निवेशक की नियुक्ति की कमीषी

2415. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सुपर बाजार, नई दिल्ली में अब तक कितनी पूंजी लगाई है; और

(ख) सुपर बाजार, नई दिल्ली के निदेशक की नियुक्ति सम्बन्धी मापदंड क्या है

और भ्रष्टाचारियों द्वारा निदेशक के चुनाव की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथसिंह श्री ० सिन्धे) : (क) भारत सरकार ने कोम्पारेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली में अब तक षष्ठ पूंजी भंडान के रूप में 66.76 लाख रुपये की धन राशि लगाई है। इसके अतिरिक्त, 77.43 लाख रुपये की राशि ऋण और 7.22 लाख की अनुदान के रूप में दी गई थी (ऋण में से सुपर बाजार ने वापसी-प्रदायगी की समय-धनुसूची के अनुसार 19.03 लाख रु० की राशि लौटा दी है)।

(ख) कोम्पारेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली को उप-विधियों के अनुसार प्रबन्ध समिति के नौ सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं और शेष छः सरकार के अलावा दूनने भ्रष्टाचारियों द्वारा निर्वाचित किये जाने होते हैं। नामित निदेशकों का चयन सरकार द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि वे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों जिनमें ग्रन्थ गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ-साथ एक संभव सदस्य और राष्ट्रीय महकारी उपभोक्ता परिषद, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली प्रबन्धन और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होने हैं।

Short Supply of Small Tractor in Madhya Pradesh

2417. SHRI G. C. DIXIT: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether small tractors are in short supply in Madhya Pradesh as compared to the other States; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SHRI B. P. MAURYA): (a) and (b). Among small tractors, the Madhya Pradesh Agro Industry Corporation Ltd., Bhopal is selling H.M.T. Zetor-2511 tractors. Against an order for 189 tractors placed by the Corporation, the HMT have supplied 149 tractors upto 28-2-74. The balance is expected to be supplied during March/April, 1974.

Handing over of Uneconomic Routes run by D.T.C. to Private Operators

2418. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a proposal is under the consideration of Government to hand over the uneconomic routes at present run by the Delhi Transport Corporation to the private operators; and

(b) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Taking over of Slum Clearance and Improvement Scheme from DMC

2419. SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the slum clearance and improvement schemes in the Capital have been taken over from the Delhi Municipal Corporation; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(SHRI OM MEHTA): (a) Yes, Sir.

(b) The Scheme was not implemented satisfactorily by the corporation.

Development of Public Transport System in the Metropolitan Cities

2420. SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) the amount of money allotted to the Ministry out of the collections made from the sale of petrol during 1973 for development of public transport system in the Metropolitan cities;

(b) whether city-wise allocations have been made for this purpose, and if so, the figures thereof; and

(c) the additional buses that will be added to each city under this programme during 1974?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) to (c). No funds have been placed at the disposal of Ministry of Shipping and Transport out of the revenue from the recent additional levies on petrol. However, it has been agreed that Government of India may consider providing some financial assistance for improving the public transport system, especially in metropolitan cities, which have come under pressure following the shift in traffic from personalised transport to public transport, in view of the hike in petrol prices. Proposals were invited from City Transport Undertakings in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras for financial assistance for implementation of short term schemes, which are expected to give quick benefits to the commuters. The details of the schemes proposed by